राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधी परियोजना रिपोर्ट

818. **श्री भंवर लाल पवार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिये विश्व बैंक से कर्जा प्राप्त करने हेतु एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; यदि हां, तो कितनी राशि एवं कितनी अवधि के लिये ऋण की मांग की गई है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आवंटन का कार्य पूरा कर लिया है ; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि भूमि आवंटन के कार्य में विलम्ब के कारण राजस्थान के हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और इससे राजस्थान को भारी क्षति हुई है एवं भविष्य में भी होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) राज्य सरकार ने मार्च, 1988 के पश्चात् शेष कार्यों को पूरा करने के लिए परियोजना के लिए बाह्य सहायता मांगते हुए 2130.90 करोड रुपए की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए जाने और परियोजना स्वीकृत होने के बाद ही ऋण की राशि और इसकी आवश्यकता की अवधि निश्चित की जा सकती है।

(ख) और (ग) : चरण II क्षेत्र में उपनिवेशन संबंधी कार्य ने अभी गति नहीं पकड़ी है क्योंकि इस क्षेत्र की स्थितियां अधिक कटु हैं और सडकों, पेय जल आपूर्ति जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास उपनिवेशन कार्यकलापों से पहले किया जाना है। मुख्य नहर दिसम्बर, 1986 में ही पूरी हुई थी। चरण दो में कुल 8.1 लाख हैक्टेयर में से मार्च, 1987 तक 75,000 हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई है। राज्य सरकार का सातवीं योजना के अन्त तक सिंचाई के लिए कुल 2.31 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी० सी० ए०) खोलने का प्रस्ताव है। शेष क्षमता आठवीं योजना के अन्त तक सृजित किए जाने की सम्भावना है।

जाफराबाद, दिल्ली में फ्लैटों का आवंटन

819. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री 20 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2778 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाफराबाद में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली एवं नगर निगम द्वारा पानी की व्यवस्था न किए जाने के बावजूद डी. डी. ए. वहां एल० आई० जी० फ्लैटों को जबरदस्ती आवंटित कर रहा है और वहां के अलाटी उक्त फ्लैटों के रद्द हो जाने की आशंका से अपना कब्जा ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों में बिना बिजली व पानी की सुविधा के कितने व्यक्तियों ने कब्जा ले लिया है ;

(ग) क्या डी० डी० ए० भी आवंटियों द्वारा बिजली और पानी की सुविधा के बिना कब्जा न लेने पर फ्लैटों का आवंटन रद्द करने की धमकी दे रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिन्होंने बिजली एवं पानी की सुविधा न होने पर भी फ्लैट की धनराशि जमा करा दी है और कब्जा नहीं लिया है, उक्त राशि पर ब्याज दे रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जाफराबाद में आवंटन के लिए फ्लैट उपलब्ध होने के पश्चात् आवंटन पत्र तैयार किए गए हैं तथा संबंधित आवंटी को कब्जा पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह सही नहीं है कि जाफराबाद में इन निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के किसी आवंटिती को कब्जा लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

(ख) 18 (अठारह केवल)।

(ग) ऐसे मामलों में फ्लैटों को निरस्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) यदि आवंटियों ने भुगतान कर दिए हैं और बिजली, पानी सीवर, लाइन जोडना आदि जैसी सेवाओं के प्रावधान सहित फ्लैटों के अपूर्णता के कारण कब्जा नहीं दिया जाता है, तो पूर्णता की तारीख तक आवंटियों के धरोहर राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है।

Action taken against the officials of NCCF involved in irregularities

820. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 2204 given in the Rajya Sabha on the 8th May, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that the CBI submitted a report to Government in 1980 holding certain officers of NCCF guilty of committing serious malpractices in the export of bicycles to Iran;

(b) whether it is a fact that Managing Director, NCCF in its report to the Executive Committee Meeting in October, 1979 had held certain officers responsible for importing inferior variety of Dry Fruits from Iran in 1978-79 thereby causing huge losses to NCCF;

(c) whether it is also a fact that a syndicate of officers in NCCF was found to be involved in corrupt practices in a number of Import deals recently; and

(d) if so, what are findings of the CBI and the Departmental enquiries thereof and what action has been taken against the officers involved?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) In December 1980, the CBI forwarded a report to the Government of India in which an exe-officer of DSIDC, who was then working in the NCCF, was found to be involved in some irregularities in a deal of export of bicycles to Iran by DSIDC.

(b) Yes, Sir, but the charged officer was exonerated subsequently as per further report of two Directors who were appointed by the Executive Committee of NCCF to look into this matter.

(c) and (d) Enquiry reports have shown involvement of certain officers in committing irregularities in some import deals. The acts of omission/commission have been referred to the parent Departments of the officers who were on deputation in NCCF for taking necessary action. Departmental action has been initiated against the officers who are still working in NCCF. One case has been referred to the CBI whose report in the matter has not yet been received.

Slum Board for Delhi

821. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has recently recommended to the Central Government for the establishment of an autonomous slum board;